राज्यपाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

स्वतंत्रता दिवस – 2021

राज्यपाल ने झण्डारोहण किया

—

जयपुर, 15 अगस्त। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने रविवार को यहां राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झण्डारोहण किया। इसके उपरांत राज्यपाल श्री मिश्र ने पांचवी बटालियन आरएसी गारद की सलामी ली।

इस अवसर पर राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राजभवन परिसर स्थित राजकीय विद्यालय के उच्च प्राप्तांक वाले छात्र–छात्राओं को पुरस्कार तथा मिठाई वितरित कर उनका उत्साहवर्द्धन किया।

कोरोना महामारी के चलते राजभवन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संक्षिप्त एवं सादगीपूर्ण तरीके से झण्डारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राजभवन परिसर के उद्यान में कदम्ब और तालवृक्ष का पौधारोपण किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री सुबीर कुमार, प्रमुख विशेषाधिकारी श्री गोविन्द राम जायसवाल सहित राजभवन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

राज्यपाल श्री मिश्र का स्वाधीनता दिवस पर संदेश

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के संदेश का वाचन जिला स्तरीय समारोहों में करवाया गया।

राज्यपाल श्री मिश्र का स्वाधीनता दिवस पर संदेश अविकल रूप से प्रस्तुत है–

- आज हमारा देश हर्ष और उल्लास के साथ 75 वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मैं इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
- इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले रणबांकुरों, अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनके त्याग, संघर्ष और बलिदान से हम विश्व के सबसे बडे लोकतंत्र में रहकर गौरवान्वित हैं।
- मैं हमारे बीच में मौजूद हमारे प्रेरणा स्त्रोत स्वतंत्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता हूं एवं उनके स्वस्थ और दीघार्यु होने की कामना करता हूं।
- देश की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखने के लिए सरहद पर शहादत देने वाले बहादुर सैनिकों, अर्द्ध सैनिक बल के जवानों तथा पुलिस के जांबाज सिपाहियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात सभी जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

- आप सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरी दुनिया में विकट परिस्थितियां बनी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना काल में भी राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन देने के संकल्प के साथ विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर रही है।
- ''राजस्थान सतर्क है'' के सूत्र को लेकर राज्य सरकार ने कोरोना की चुनौती को अवसर में बदलते हुए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के सार्थक प्रयास किये हैं। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का ही परिणाम रहा कि राजस्थान की रिकवरी रेट सबसे बेहतर रही और मृत्युदर भी कम रही।
- प्रदेश में कोरोना जांच की सुविधा नहीं होने से पहले सेम्पल पुणे भेजे जाते थे। वर्तमान में राज्य में 70 लैब्स स्थापित कर जांच क्षमता प्रतिदिन 1 लाख 45 हजार की जा चुकी है।
- कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अस्पतालों में बेड्स की संख्या में निरन्तर वृद्धि की गयी। प्रथम लहर में मात्र 8 हजार 529 ऑक्सीजन बेड्स थे। द्वितीय लहर में ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाकर 21 हजार 261, आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाकर 2 हजार 976, वैन्टीलेटर्स की संख्या बढ़ाकर 2 हजार 534 एवं सामान्य बेड्स की संख्या दोगुनी करके 14 हजार 465 की जा चुकी है।
- कोरोना संक्रमण की प्रारम्भिक अवस्था में पहचान कर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिये 27 हजार टीमें गठित कर घर–घर सर्वे किया गया एवं 18 लाख से अधिक मेडिसिन किट वितरित किये गये।
- द्वितीय लहर के दौरान राज्य सरकार द्वारा समस्त संसाधनों का उपयोग करते हुये मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित की गई।
- समस्त बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। जिससे प्रदेश में ऑक्सीजन का उत्पादन एवं स्टोरेज क्षमता 20 मीट्रिक टन से 1000 मीट्रिक टन हो जाएगा।
- ऑक्सीजन प्लांट एवं ऑक्सीजन कॉनसनट्रेटर से पीएचसी स्तर तक ऑक्सीजन बेड्स लगाए जाएंगे एवं ऑक्सीजन बेड्स की संख्या 60000 की जा रही है।
- मेडिकल कॉलेज अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर में 50–50 बेड्स के नवीन आईसीयू एवं 20–20 बेड्स के एनआईसीयू तथा जिला चिकित्सालय भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, डूंगरपुर, बाड़मेर एवं सीकर में 30–30 बेड्स के आईसीयू का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
- प्रदेश में जीनोम सिक्वेन्सिंग प्रारम्भ की जा चुकी है तथा बजट 2021–2022 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एण्ड वायरोलॉजी की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में अधिसूचित करने में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बना। राजकीय एवं चिरंजीवी योजना से जुड़े चिकित्सालयों में ब्लैक फंगस का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है।
- राज्य सरकार ने पूरी गंभीरता से कोरोना पर नियंत्रण के प्रयास किए। दवाईयों की कमी होने पर चार्टर्ड प्लेन से दवाईयां मंगवाई गई।
- राजस्थान 50 लाख टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना व एक करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बना। प्रदेश में 5 अगस्त 2021 तक कुल 3 करोड 42 लाख से अधिक व्यक्ति टीकाकृत किये जा चुके हैं।
- हमारे कुशल प्रबंधन एवं स्वास्थ्यकर्मियों की लगन का प्रमाण है कि प्रदेश में वैक्सीन की एक भी डोज खराब नहीं हुई है। प्रतिदिन 15 लाख टीकाकरण किये जाने की क्षमता विकसित की जा चुकी

है। निःशक्तजनों, कैदियों, भिखारियों, पाक विस्थापितों के लिए विशेष शिविर आयोजित किये जा रहे हैं।

- कोविड–19 महामारी की रोकथाम एवं प्राकृतिक आपदाओं में सहायता व क्षमता संवर्धन के लिए इस वित्तीय वर्ष में 918 करोड़ 70 लाख रूपये की राशि आवंटित की जा चुकी है।
- कोरोना महामारी के दौरान 5 चरणों में 5 हजार 500 रूपये प्रति परिवार के अनुसार लगभग 33 लाख परिवारों को 1 हजार 866 करोड़ रूपये की सहायता दी गयी है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत 53 करोड ़रूपये व्यय कर 135 अनाथ बच्चों, 5 हजार 291 विधवा महिलाओं एवं 3 हजार 990 विधवा महिलाओं के बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

- ''यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज'' को लागू करने की दिशा में 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की गयी। जिसके तहत 5 लाख रूपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य के 1 करोड़ 32 लाख से अधिक परिवारों को योजना से जोड़ कर 1 मई 2021 से 29 जुलाई 2021 तक 1 लाख 21 हजार 436 मरीजों के इलाज पर 156 करोड़ रूपये का व्यय किया जा चुका है।
- राज्य के कार्मिकों व पेंशनर्स के कल्याण हेतु 3 हजार करोड़ रूपये से कार्मिक कल्याण कोष का गठन किया गया है। कार्मिकों एवं पेंशनर्स को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं को सीजीएचएस की तर्ज पर कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरजीएचएस प्रारम्भ की गयी है।
- निरोगी राजस्थान के संकल्प को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक–एक महिला व पुरूष स्वास्थ्य मित्र का चयन कर 79 हजार 731 स्वास्थ्य मित्रों को एवं शहरी वार्ड में एक–एक महिला व पुरूष स्वास्थ्य मित्र के लिये 14 हजार स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर 13 हजार 657 स्वास्थ्य मित्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनान्तर्गत वर्तमान में आवश्यक दवा सूची में 971 प्रकार की औषधियां, सर्जिकल्स एवं सूचर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाया गया है । प्रतिदिन 1 लाख 25 हजार से अधिक निःशुल्क जांचों से जनता को लाभान्वित किया जा रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 891 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विकसित करने की दिशा में अब तक 198 आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन किया जा चुका है।
- सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में 10 करोड़ की लागत से एडवांस मेडिकल आईसीयू एवं 2 करोड़ की लागत से स्ट्रोक आईसीयू का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जोधपुर के मथुरा दास माथुर चिकित्सालय में पिडीयाट्रिक केथ लेब एवं अजमेर के जेएलएन चिकित्सालय में केथ लेब स्थापित की जा चुकी है।
- राजस्थान राज्य में आयुष नीति–2021 जारी की गयी तथा पहली बार राजकीय क्षेत्र के नवीन आयुर्वेद एवं योग के एकीकृत महाविद्यालय 6 जिलों जयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर एवं सीकर में तथा होम्योपैथिक महाविद्यालय जोधपुर एवं अजमेर जिले में स्थापित किये जा रहे हैं।

- औषधीय पौधों के संरक्षण एवं आमजन के स्वास्थ्य रक्षण हेतु ''घर–घर औषधि योजना'' का शुभारम्भ किया गया है। वन विभाग की पौधशालाओं से 5 वर्षों में 3 बार प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ के 8–8 औषधीय पौधे वितरित किये जाएंगे। योजना में कुल एक करोड़ 26 लाख परिवारों को 30 करोड़ पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी फसल 2020–21 में 40 लाख 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र की फसलों को बीमित कर 40 लाख 21 हजार ऋणी कृषकों तथा 19 हजार गैर ऋणी कृषकों का बीमा किया गया। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 11 हजार 418 करोड़ राशि के बीमा क्लेम वितरित किए जा चुके हैं।
- किसानों को वर्ष 2020–21 में 21 लाख 58 हजार मैट्रिक टन यूरिया, 7 लाख 39 हजार मैट्रिक टन डीएपी एवं खरीफ सीजन में माह अप्रेल 2021 से जून 2021 तक 3 लाख 23 हजार मैट्रिक टन यूरिया एवं 1 लाख 47 हजार मैट्रिक टन डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की मांग के अनुरूप आपूर्ति करवाई गयी।
- कृषक हितों को ध्यान में रखते हुए सहकारी बैंकों के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में जून 2021 तक लगभग 6 हजार 268 करोड़ रूपये के अल्पकालीन, 46 करोड़ रूपये के मध्यकालीन एवं 20 करोड़ रूपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये जा चुके हैं।
- बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, निर्धन, बेघर एवं ट्रांसजेण्डर्स आदि वंचित वर्ग को सुविधाएं प्रदान करने के लिये सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना–2021 लागू की गयी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 86 लाख लोगों को आर्थिक सम्बल प्रदान किया जा रहा है। पेंशन के रूप में इस वित्तीय वर्ष में अब तक 3 हजार 351 करोड़ रूपये से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है।
- अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में 36 निर्माण कार्यों के लिये 5 करोड़ 39 लाख रूपये स्वीकृत किये गये तथा इस वित्तीय वर्ष के लिए 25 करोड़ रूपये की घोषणा की गयी है।
- महिलाओं एवं बालिकाओं के सम्पूर्ण कल्याण व समग्र विकास हेतु नवीन राज्य महिला नीति–2021 जारी की गयी है। आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों के मानदेय में इस वित्तीय वर्ष से राज्य सरकार द्वारा दी जा रही राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- महात्मा गांधी नरेगा योजना में 38 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध करावाकर 9 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जिस पर 2,653 करोड़ रूपये व्यय हुए हैं।
- राजीविका योजनान्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के परिवारों की महिलाओं को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख 4 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 24 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा गया है। इनमें से 1 लाख 31 हजार समूह की महिलाओं को रोजगार हेतु 1 हजार 501 करोड़ रूपये का बैंक ऋण उपलब्ध करवाया जा चुका है।
- राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण में जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्यों पर लगभग 468 करोड़ रूपये व्यय कर 39 हजार 600 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।
- आवासन मंडल द्वारा प्रताप नगर में लगभग 65 हजार वर्गमीटर भूमि पर कोचिंग हब, लगभग 52 एकड़ भूमि पर मानसरोवर में सिटी पार्क तथा जयपुर में 3, जोधपुर व कोटा में एक–एक फूड कोर्ट

विकसित किये जा रहे हैं। जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए आरसीए को भूमि उपलब्ध करवाई गई है।

- इन्दिरा रसोई योजना में 358 रसोइयों के माध्यम से जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक बैठाकर 8 रूपये में शुद्ध, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 3 करोड़ 65 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है।
- कोविड के कारण मृत्यु होने पर पार्थिव देह के निःशुल्क एम्बूलेंस से परिवहन एवं निर्धारित प्रॉटोकॉल के तहत सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था की गई।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वच्छकार कल्याण परिकल्पना को साकार करने एवं सीवरेज सफाई के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 176 करोड़ रूपये की लागत से उपकरण उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा में पार्किंग, चिकित्सा, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, खेलकूद, शहरी आधारभूत सुविधाओं के लिये 1 हजार 700 करोड़ रूपये व्यय कर राजस्थान निर्धारित मापदण्डों में देशभर में प्रथम स्थान पर है। आरयूआईडीपी तृतीय एवं चतुर्थ चरण के कुल 26 शहरों में 6 हजार 566 करोड़ रूपये से अधिक के सीवरेज व जलप्रदाय कार्य प्रगतिरत हैं।
- शहरी और ग्रामीण लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 2 अक्टूबर 2021 से ''प्रशासन शहरों के संग''एवं ''प्रशासन गाँवों के संग'' अभियान प्रारम्भ किया जायेगा। ''प्रशासन शहरों के संग'' में 10 लाख से अधिक पट्टे दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पहली बार 500 करोड़ रूपये के पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया है तथा 300 करोड़ रूपये पर्यटन स्थलों पर आधारभूत विकास कार्यों और 200 करोड़ रूपये मार्केटिंग व ब्रांडिंग पर खर्च किये जायेंगे।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्तीवर्ष समारोह आयोजन की श्रृंखला में 12 मार्च 2021 को दांडी यात्रा, 23 मार्च 2021 को शहीद दिवस के अवसर पर जनपथ स्थित अमर जवान ज्योति स्मारक पर देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम किए गए। राजस्थान के 220 स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित वर्चुअल प्रदर्शनी 18 जुलाई 2021 को आयोजित की गई एवं 6 अगस्त 2021 को देशभक्ति गीतों पर आधारित म्यूजिकल बैण्ड का कार्यक्रम ''मां तुझे सलाम'' आयोजित किया गया।
- मुख्यमंत्री कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से प्रदेश के जरूरतमंद कलाकारों को प्रति कलाकार 5 हजार रूपये की सहायता राशि दी जा रही है। जवाहर कला केंद्र में विशेषज्ञ कलाकारों के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर मानदेय भी दिया जा रहा है।राज्य की 9 जन–जाति जिलों की, 9 कलाओं की ऑनलाइन कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।
- विद्युत उत्पादन क्षमता में गत ढाई वर्षों में 2 हजार 30 मेगावॉट की वृद्धि कर अब इसकी क्षमता 22 हजार 369 मेगावॉट कर ली गई है। इसके अतिरिक्त 660 मेगावॉट की सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की इकाई–8 को भी सिंक्रोनाइज कर दिया गया है। विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 477 ग्रिड सब–स्टेशन स्थापित किये गए एवं अब तक 2 लाख 4 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।
- ''मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना'' मई 2021 से लागू की गई। कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 1 हजार रूपये तक व प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रूपये तक अनुदान दिया जा रहा है। इस

योजना में सालाना 1 हजार 450 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

- विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिये जाने के लिए 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांव एवं कस्बों में अगले 2 वर्षों में 1 हजार 200 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित करने के लिए प्रथम चरण में 348 विद्यालयों का चयन कर प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। अब तक जिला मुख्यालयों एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित 201 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को 5 करोड़ 85 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।
- राजकीय विद्यालयों की बढ़ती गुणवत्ता से शिक्षा सत्र 2020–21 में राजकीय विद्यालयों में गत वर्ष की तुलना में नामांकन में लगभग 6 लाख 50 हजार की बढ़ोतरी हुई है।
- कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा की निरन्तरता बनाये रखने के लिए ई–कक्षाएं प्रारम्भ कर स्माइल, शिक्षावाणी, शिक्षादर्शन, हवामहल कार्यक्रम एवं ई–कक्षा डिजिटल कंटेट द्वारा ऑनलाइन शिक्षण प्रदान किया जा रहा है। स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत रही कक्षा–12 की पात्र बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार सहित अन्य योजनाओं में भी शामिल किया गया है।
- प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 35 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये तथा 5 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। ढाई साल में 123 नए कॉलेज खोले गए है जिनमें 32 महिला कॉलेज है।
- जिन विद्यालयों की 11 वी एवं 12 वीं कक्षा में 500 छात्राऐं होगी उन स्कूलों को गर्ल्स कॉलेज में क्रमोन्नत किया जाएगा। अभी तक 26 विद्यालयों को कॉलेज में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।
- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मेधावी छात्राओं को कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना के तहत 10 हजार से अधिक स्कूटी बांटी जा रही हैं।
- तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2021–22 में 4 नये राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मण्डोर, पिलानी, नावां एवं उच्चैन में स्थापित किये जा रहे हैं।
- प्रदेश में किसानों को राजस्व मामलों में राहत प्रदान करने की दिशा में इस वित्तीय वर्ष में एक अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय, 12 उपखण्ड, 30 तहसील एवं 27 उप तहसील कार्यालयों का सृजन किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित किये जाने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना जारी की गई है।
- शहीद सैनिकों के आश्रित माता–पिता को सावधि के आधार पर प्रदान की जा रही 3 लाख रूपये की राशि को बढाकर 5 लाख रूपये कर दी गई है। इसी प्रकार 1 अप्रेल 1999 से पूर्व के शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं तथा अविवाहित शहीद सैनिकों के माता–पिता को देय सम्मान भत्ता राशि को भी 3 हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 5 हजार रूपये प्रतिमाह किया गया।
- गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिये इस वित्तीय वर्ष में गोशाला तथा कांजी हाउस में आवासित गोवंश के भरण पोषण हेतु लगभग 305 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया। प्रत्येक ब्लॉक में 1 करोड़ 50 लाख रूपये की लागत से तैयार किये गये मॉडल के आधार पर नन्दीशाला बनाये जाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 111 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 92 हजार 936 युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा 80 हजार 807 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आर्थिक रूप से कमजोर पुरूष अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की एवं महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट दिए जाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
- मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के प्रारम्भ से जून 2021 तक 998 करोड़ 51 लाख रूपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित कर लगभग 2 लाख 52 बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। कौशल विकास की राज्य तथा केंद्र की 6 योजनाओं के माध्यम से 17 दिसम्बर 2018 से अब तक 1 लाख 56 हजार से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जा चुके हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार लगभग 250 करोड़ रूपये का व्यय वहन कर अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को मार्च 2019 से 1 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध करा रही है। वर्तमान में अन्त्योदय योजना के तहत 24 लाख, बीपीएल के तहत 98 लाख तथा स्टेट बीपीएल के तहत 24 लाख लाभार्थियों को गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है।
- प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2021–22 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 23 लाख 40 हजार मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। प्रदेश में लगभग 2 लाख 27 हजार किसानों को डिजिटल माध्यम से 4 हजार 620 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका हैं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित 114 योजनाओं व सेवाओं का लाभ हस्तांतरण करने के लिए उन्हें जन–आधार प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। योजनान्तर्गत 31 जुलाई 2021 तक 1 करोड़ 84 लाख से अधिक परिवारों के लगभग 6 करोड़ 94 लाख व्यक्तियों का नामांकन कर जन आधार कार्ड जारी किये जा चुके हैं।
- ई–गवर्नेंस संसाधनों के माध्यम से सुशासन के लिये प्रतिबद्ध राज्य सरकार द्वारा अंतिम छोर तक आमजन को सहज सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 61 हजार 616 एवं शहरी क्षेत्र में 26 हजार 340 ई–मित्र कियोस्क स्थापित कर 475 से अधिक सेवायें उपलब्ध करवायी जा रही हैं।
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 के तहत जुलाई 2021 तक प्रस्तावित 88 हजार 956 करोड़ रूपये निवेश की 4 हजार 915 इकाइयों को पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जा चुके हैं। एकल खिड़की व्यवस्था के तहत जुलाई 2021 तक 9 हजार 234 करोड़ रूपये से अधिक के प्रस्तावित निवेशों के 1 लाख 6 हजार 454 प्रस्तावों की अनुमति जारी की जा चुकी है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ''उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल'' में जुलाई 2021 तक लगभग 17 लाख व्यक्तियों को रोजगार तथा 26 हजार1 94 करोड़ रूपये की पूंजी निवेश के लगभग 2 लाख 57 हजार उद्यमों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा चुका है।
- देश की प्रथम रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार तत्परता से प्रयासरत है। परियोजना पर विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जून 2021 तक 8 हजार 41 करोड़ रूपये से अधिक व्यय किया जा चुका है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज हेतु ओएएलपी पॉलिसी में 2 नए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक बीकानेर व जोधपुर क्षेत्र में आवंटित किए गए हैं।

- उच्चतम न्यायालय एवं NGT द्वारा बजरी पर रोक लगाने के पश्चात् बजरी का उचित विकल्प उपलब्ध कराने व एम–सैण्ड को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एम–सैण्ड नीति जारी की गई है।
- खातेदारी भूमि पर खातेदारों की रजिस्टर्ड सहमति के आधार पर ही खनन पट्टा जारी करने हेतु नई नीति जारी की गई है। इस वित्तीय वर्ष में अप्रधान खनिज के 6 हजार 148 हैक्टेयर क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। शीघ्र ही इनके 1 हजार 950 प्लॉट बनाकर ई–ऑक्शन किया जाएगा।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को एसजीएसटी राशि का पुनर्भरण दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बैट्री क्षमता के अनुसार अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
- खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में 158 अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी जा चुकी है।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राज्य के सड़क तन्त्र को मजबूत करने की दिशा में 14 हजार 354 करोड़ रूपये का व्यय कर 4 हजार 818 किलोमीटर नवीन सड़कों, 775 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों, 4 हजार 18 किलोमीटर राज्य राजमार्गों व 23 हजार 254 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय फेज के प्रथम चरण में 2 हजार 510 किलोमीटर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। राज्य में 5 आरओबी एवं 19 आरयूबी के निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 23 आरओबी व 37 आरयूबी के निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं।
- आमजन को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वृहद् पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से 15 शहरों, 3 हजार 693 गांवों एवं 3 हजार 148 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है तथा 1 हजार 14 आरओ प्लांट्स एवं 1 हजार 696 सौर ऊर्जा आधारित डी–फ्लोरीडेशन संयंत्रों के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- जल जीवन मिशन योजना के तहत 101 वृहद् परियोजनाओं सहित 7 हजार 574 योजनाएं स्वीकृत करने से 27 हजार गांवों के 70 लाख परिवारों को नल से जल सुलभ करवाया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष के लिये 12 हजार 500 करोड़ की कार्य योजना अनुमोदित की जा चुकी है। वर्तमान में 20 लाख 58 हजार ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर इस वित्तीय वर्ष में जून 2021 तक लगभग 652 करोड़ रूपये व्यय कर 4 हजार 580 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गयी है। सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये इंदिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर की लगभग 70 किलोमीटर की लंबाई में रीलाइनिंग के कार्य करवाये जा चुके हैं।
- सिचिंत क्षेत्र विकास के तहत प्रगतिरत गंगनहर फेज द्वितीय, सिद्धमुख, अमरसिंह, जस्साना एवं भाखड़ा नहर परियोजना पर इस वित्तीय वर्ष में जून 2021 तक 12 हजार 141 हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं।
- पंजाब सरकार के साथ समझौता कर 60 दिन की ऐतिहासिक नहरबंदी ली गई। इस दौरान इन्दिरा गांधी नहर में 47 किलोमीटर रिलाईनिंग का कार्य किया गया।
- वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना शुरू कर पात्र पत्रकारों को 15 हजार रूपये प्रतिमाह सम्मान राशि दी जा रही है।

- पुलिस थाने पहुंचने वाले प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को सुविधाजनक एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने के लिये सभी पुलिस थानों में स्वागत कक्षों का निर्माण कराने की दिशा में अब तक 430 थानों में स्वागत कक्षों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 149 थानों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- कानून एवं शांति व्यवस्था को माकूल बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बहुरंगी संस्कृति एवं कौमी एकता हमारी आत्मा है। सामाजिक समरसता, पारस्परिक सौहार्द, भाईचारा व अनेकता में एकता को बनाए रखकर ही हम समृद्ध समाज और सम्पन्न प्रदेश के निर्माण में सहभागिता कर सकते हैं।
- राज्य सरकार एक विस्तृत विजन के साथ समृद्ध, विकसित और आधुनिक राजस्थान के निर्माण के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है।
- दाण्डी यात्रा की 91वीं वर्षगांठ 12 मार्च 2021 से प्रारम्भ हो गयी है और यह 15 अगस्त 2023 तक चलेगी। इस अवसर पर हम सबको स्वाधीनता संग्राम में हुए बलिदानों और तपस्याओं को नमन कर राष्ट्रभक्ति के साथ उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना है।
- आइए, आप और हम सब मिलकर लोकतंत्र की रक्षार्थ हमारी एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने के साथ ही श्रेष्ठ, सशक्त एवं निरोगी राजस्थान के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं।

जय हिन्द।

———